



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 243 राँची, मंगलवार, 13 मार्च, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

19 दिसम्बर, 2017

कृपया पढ़ें:-

उपायुक्त, लोहरदगा का ज्ञापांक-324/विधि, दिनांक 18 अगस्त, 2001 एवं पत्रांक-282/विधि, दिनांक 24 जुलाई, 2002 तथा पत्रांक-462/विधि, दिनांक 3 दिसम्बर, 2004

संख्या- 5/आरोप-1-708/2014 का.-12408-- श्री शंकर प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-419/03, गृह जिला-भागलपुर), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा के विरुद्ध उपायुक्त, लोहरदगा के ज्ञापांक-324/विधि, दिनांक 18 अगस्त, 2001 द्वारा इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत बिचैलियों एवं सरकारी सेवक के साँठगाँठ से अवैध रूप से लाभकों से दिये गये

अग्रिम को ठगने तथा नजायज ढंग से जबरन वसूली करने संबंधी आरोपों हेतु लाभुकों द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध शिकायत पत्र के आधार पर दर्ज सेन्हा थाना कांड सं०-70/97, दिनांक 19 दिसम्बर, 1997 में अभियोजन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया। विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड द्वारा कतिपय पृच्छा के आलोक में पुनः उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-282/विधि, दिनांक 24 जुलाई, 2002 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध संबंधित थाना कांड में दर्ज प्राथमिकी की प्रति तथा कांड दैनिकी उपलब्ध कराया गया। तत्पश्चात् विधि विभाग के आदेश सं०-136/जे०, दिनांक 18 दिसम्बर, 2002 द्वारा इनके विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी।

उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-462/विधि, दिनांक 3 दिसम्बर, 2004 द्वारा उक्त अभियोजन स्वीकृत्यादेश में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में विधि विभाग के आदेश सं०-14/जे०, दिनांक 17 जून, 2005 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध संशोधित अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विशेष न्यायाधीश (निगरानी), राँची ने उक्त थाना कांड से संबंधित Spl. Case No.20/2005 में दिनांक 26 मई, 2014 को पारित न्यायादेश में श्री सिंह को आरोप मुक्त कर दिया है।

अतः समीक्षोपरांत, विशेष न्यायाधीश (निगरानी), राँची द्वारा दिये गये न्यायादेश के आलोक में मामले को संचिकास्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,

सरकार के संयुक्त सचिव।
